'पड़ोसी देशों से रैस्क्यू अभियान में सहायता नहीं चाहिए'

नेपाल सरकार ने इस घोषणा के साथ ही यह भी कहा कि वो आर्थिक सहायता व खाद्य सामग्री व दवाओं की मदद लेने को तैयार है

■ नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका व बाँग्लादेश ने तलाशी अभियान में सहायता टीमें भेजने की पेशकश की थी, कुछ देशों ने तलाशी के लिए हैलीकॉप्टर देने की पेशकश भी की थी, पर, नेपाल ने इन्कार कर दिया।

■ नेपाल के विदेश मंत्रालय के एक अफसर ने बताया कि सरकार का मानना है कि नेपाल की सेना तलाशी अभियान चलाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था, तब दूसरे देशों से हैलीकॉप्टर व सैन्य बचाव टीमें आई थीं, जिससे एयरपोर्ट्स, सड़कों आदि पर भारी भीड़ हो गई थी। इस बार नेपाल सरकार ऐसा कुछ नहीं चाहती है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 अगस्त। नेपाल ने भारत, चीन और कई अन्य देशों की ओर से भोटे कोशी बाढ़ के बाद लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हेलीकॉप्टर और प्रशिक्षित दल भेजने की पेशकश को ठुकरा दिया है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि उसकी सुरक्षा एजेंसियां बचाव अभियान चलाने में सक्षम हैं और उसने सैकड़ों लापता विदेशी नागरिकों से जुड़ी जानकारी के समन्वय के लिए एक केन्द्रीय व्यवस्था बनाई है।

जहाँ नेपाल, सरकार के माध्यम से भेजी जाने वाली राहत सामग्री और आर्थिक सहायता के रूप में विदेशी मदद स्वीकार कर रहा है, वहीं उसने विदेशी खोज और बचाव सहायता लेने से इनकार कर दिया है। काठमांडू के इस फैसले के पीछे अतीत का एक अनुभव भी है।

काठमांडू स्थित समाचार माध्यमों, द काठमांडू पोस्ट और हाम्रो पात्रो के अनुसार, भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और बांग्लादेश उन देशों में शामिल थे, जिन्होंने आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से खोज और बचाव दल भेजने की पेशकश की थी। अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी काठमांडू से संपर्क किया था, जबकि कुछ सरकारों ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रशिक्षित हेलीकॉप्टर और कर्मचारियों की पेशकश की थी।

ताजा आंकडों के अनुसार, अचानक आई बाढ़ में करीब 400 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,300 से अधिक लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लापता लोगों में कैलाश मानसरोवर और गोसाईं कुंड की यात्रा कर रहे भारतीयों सहित, सैकड़ों विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। कम से कम 84 भारतीयों को बचाया जा चुका है और सैकड़ों अभी भी लापता हैं।

"पड़ोसी पहले" नीति के तहत भारत ने शुरुआत में 10 टन मानवीय सहायता भेजी और इसके बाद सैन्य परिवहन विमानों से 37.5 टन और राहत सामग्री भेजी। सी-130जे और सी-17 विमानों से भेजी गई सामग्री में अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट, सौर लैंप, दवाइयां और भोजन के पैकेट शामिल थे। नई दिल्ली ने नेपाल को बैली और पहले से तैयार ट्रस पुल देने की भी पेशकश की है, जहां दर्जनों छोटे-बड़े पुल नष्ट हो गए हैं। 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के समय भारत सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देशों में शामिल था।

तो फिर काठमांडू ने भारत, चीन और अमेरिका सहित देशों से खोज और बचाव अभियान में किसी भी तरह की सहायता लेने से इनकार क्यों किया है?

नेपाल के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने "द काठमांडू पोस्ट" को बताया कि सरकार को कई देशों और संगठनों से आधिकारिक और अनौपचारिक अनुरोध मिले थे, जो अपने दल भेजने की अनुमति मांग रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है, "हालांकि, सरकार ने उन्हें बताया है कि नेपाल की अपनी सुरक्षा एजेंसियां इस अभियान को संभालने में सक्षम हैं।"

द काठमांडू पोस्ट में उद्धत विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अप्रैल 2015 में आए भूकंप के बाद नेपाल का अनुभव इस फैसले का मुख्य आधार था।

भूकंप के बाद पूरी दुनिया से बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय मदद पहुंची थी। बचाव दल, सैन्य विमान और राहत संगठन दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से नेपाल पहुंचे थे। इससे नेपाल की आपातकालीन क्षमता बढ़ी, लेकिन अचानक बडी संख्या में विदेशी दलों के पहुंचने से प्रशासन और सामान की व्यवस्था पर भी गंभीर दबाव पड़ा था।

नेपाली अधिकारियों ने पोस्ट को बताया कि विदेशी दलों के बीच आपसी होड़ और उनकी गतिविधियों के समन्वय में आई मुश्किलों ने स्थिति को और जटिल बना दिया था। उस समय हवाई अड्डे, सड़कें और संचार नेटवर्क पहले से ही दबाव में थे।

अब काठमांडू कई अलग-अलग विदेशी बचाव दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देने के बजाय स्पष्ट नेपाली नेतृत्व और नियंत्रण व्यवस्था बनाए रखकर उस स्थिति को दोबारा पैदा होने से बचना चाहता है।

नेपाल ने विदेशी खोज और बचाव सहायता लेने से इनकार किया है, लेकिन राहत सामग्री और आर्थिक सहायता के रूप में मदद स्वीकार कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली की प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हुए इस अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, "नेपाल की ओर से जो भी अनुरोध किया गया है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं।"

नेपाल ने विदेशों में स्थित अपने मिशनों से कहा है कि वे केवल प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से आर्थिक सहायता जुटाएं। इस "एक-द्वार व्यवस्था" का उद्देश्य सम्पूर्ण आर्थिक सहायता को एक जगह से नियंत्रित करना, सहायता के दोहराव से बचना और सरकार को यह तय करने की सुविधा देना है कि किन क्षेत्रों में संसाधनों की सबसे ज्यादा जरूरत है।

काठमांडू को उम्मीद है कि राहत और पुनर्निर्माण के दौरान वह आगे भी आर्थिक और सामग्री संबंधी सहायता मांगेगा। अमेरिका, ब्रिटेन और विश्व बैंक पहले ही सहायता की घोषणा कर चुके हैं, जबकि एशियाई विकास बैंक ने आपात स्थिति से आगे बढ़कर जोखिम का आकलन, शुरुआती चेतावनी प्रणाली और आपदाओं का सामना करने में सक्षम बुनियादी ढांचे के लिए सहायता देने की पेशकश की है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री निवास स्थित माँ राजराजेश्वरी मंदिर में भगवान शिव का विधि विधान से पूजन-अभिषेक एवं हवन किया। उन्होंने भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृधि और खुशहाली की निरंतर वर्षा होने की प्रार्थना की।

दिल्ली में आईएसआई के लिये जासूसी करने वाला दम्पती गिरफ्तार

यह दम्पती 2024 से सोशल मीडिया के जरिये आईएसआई एजेन्ट से सम्पर्क में है

■ आरोपियों ने 2024 और 25 में आठ भारतीय सिम कार्ड सीमा पार भेजे, जिसका उपयोग भारतीय वॉट्सएप ग्रुपों में घुसपैठ कर गुप्त जानकारी जुटाना है।

नई दिल्ली, 28 अगस्त। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन वाले एक अंतराष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है।

सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त कार्रवाई में सेल ने दिल्ली-एनसीआर में रह रहे युवा दंपति साहिल (25) और उसकी पत्नी समीरा (21) को गिरफ्तार किया है। दोनों पर पाकिस्तान स्थित इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के लिए जासूसी करने, भारतीय सैन्य ठिकानों की रेकी करने और संवेदनशील जानकारी सीमा पार भेजने का आरोप है।

पुलिस जांच के अनुसार, यह दंपति साल 2024 से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंट्स के संपर्क में था। नेटवर्क का मुख्य मकसद भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों और सैन्य गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी हासिल करना था।

आरोपियों ने भारतीय सिम कार्ड हासिल कर उन्हें दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा, जहां इन नंबरों पर वाट्स एप अकाउंट्स एक्टिवेट किए गए। पाकिस्तानी पीआईओएस ने इन नंबरों का इस्तेमाल भारतीय नागरिकों से संपर्क साधने और विभिन्न भारतीय वाट्सएप ग्रुप्स में घुसपैठ कर गुप्त जानकारी जुटाने के लिए किया।

2024 और 2025 के दौरान कुल 8 भारतीय सिम कार्ड सीमा पार भेजे गए, जिसके एवज में पाकिस्तानी हैंडलर्स ने आरोपियों को 30 हजार रुपये का भुगतान किया।

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी साहिल को भारत के विभिन्न कैंटोनमेंट (छावनी) इलाकों की रेकी करने तथा नेटवर्क में अन्य स्थानीय लोगों को भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गई थी। साहिल ने उन सैन्य कर्मियों की जानकारी भी पाकिस्तानी एजेंट्स को मुहैया कराई, जिनके खिलाफ सशस्त्र बल अधिकरण में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई लंबित थी, ताकि उनका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग या सूचना हासिल करने के लिए किया जा सके।

साहिल 2024 में इंस्टाग्राम के माध्यम से एक पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में आया था। यह संपर्क समीरा के जरिए हुआ था, जिससे बाद में साहिल ने शादी कर ली।

एजेंट ने दोनों को पीआईओ से मिलवाया, जिसने उन्हें वित्तीय मदद का झांसा देकर स्लीपर सेल और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए तैयार किया।

स्पेशल सेल ने सबसे पहले साहिल को सराय काले खां स्थित उसके निवास स्थान से हिरासत में लिया। मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ संदिग्ध चैट बरामद हुई। पूछताछ के बाद उसकी पत्नी समीरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो सिम कार्ड भेजने के काम में मुख्य भूमिका निभा रही थी।

नीट लीक के बाद केन्द्र सरकार ने एनटीए में तीन अफसर लगाये

■ ये अधिकारी एनटीए की कार्यप्रणाली को सुधारेंगे, वे तीन सप्ताह में पद संभालेंगे

नई दिल्ली, 28 अगस्त। नीट यूजी पेपर लीक होने के बाद से ही एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में एनटीए में प्रश्न-पत्र बनाने वाले 600 एक्सपर्ट को उनके पद से हटाया गया था। साथ ही सरकार की ओर से एनटीए में नए पदों पर नियुक्ति के लिए नई टीम का गठन भी किया गया था। इसी को मद्देनजर रखते हुए केन्द्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) में दो डायरेक्टर और एक ज्वाइंट डायरेक्टर को नियुक्त किया है, ताकि एजेंसी बेहतर ढ ंग से संचालित की जा सके।

एनटीए की कार्यप्रणाली को संभालने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से एजेंसी में 3 अधिकारियों की नियुक्ति की गई हैं। इसमें भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी रवि कुमार सिंह और इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी (आईपीएस) प्रसन्ना वेंकटेश वी शामिल हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, अधिकारियों को आदेश जारी होने के 3 सप्ताह के भीतर अपने पद को संभालना होगा, अन्यथा पद न ग्रहण करने पर अधिकारियों को केन्द्रीय कर्मचारी योजना से बाहर किया जा सकता है।

बता दें, साल 2016 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी अमित समदरिया को एनटीए में बतौर ज्वाइंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। हाल ही में एनटीए में प्रश्न-पत्र तैयार करने वाले 600 एक्सपर्ट को हटाया गया था। एनटीए की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने कई अहम फैसले भी लिए थे, जिसमें चार-स्तरीय पेपर चेकिंग प्रक्रिया भी शामिल थी। इस प्रक्रिया के तहत अब किसी भी परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र की जांच एक स्तर पर नहीं की जाएगी। परीक्षा को बेहतर ढ ंग से संचालित करने के लिए पेपर की जांच अब 4 फेज में पूरी की जाएगी। परीक्षा के लिए पेपर तैयार करने के बाद तथ्यों पर नजर, टाइपिंग, भाषा और अनुवाद जैसी गलतियों की जांच बारीकी से की जाएगी।

केन्द्र सरकार ने परीक्षा पर आमजन से सुझाव मांगे

नई दिल्ली, 28 अगस्त। केन्द्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में परीक्षाओं से जुड़े सुधार के लिए आमजन से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सरकार पहले ही एक उच्चाधिकार प्राप्त कार्य बल गठित कर चुकी है। यह कार्यबल सार्वजनिक परीक्षाओं में छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और सभी नागरिकों से उनके इस विषय में मत जाना चाहता है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार को एक पोस्ट कर सुझाव आमंत्रित किए हैं और इस संबंध में व्हाट्सएप, वेबसाइट, टोल फ्री नंबर और ई-मेल पता जारी किया है।

6 महीने पूरे हो गए, अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समर्थक बन गए हैं। पुराने स्थापित नेताओं के मारे जाने के बाद नए नेता सामने आए हैं, जो पिछले नेताओं से भी ज्यादा कट्टर साबित हो रहे हैं।

दूसरा घोषित उद्देश्य ईरान के परमाणु हथियारों के पूरे ढांचे को पूरी तरह नष्ट करना था, ताकि ईरान परमाणु हथियारों का बड़ा भंडार तैयार न कर सके। एक तरह से, ओबामा के दौर में हुआ बहुराष्ट्रीय समझौता भी खत्म हो गया था। इस समझौते के तहत, ईरान की परमाणु सामग्री तक पहुंच सीमित की गई थी और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए के तहत, उसकी आंतरिक परमाणु गतिविधियों की निगरानी की जाती थी। ट्रंप इस स्थापित समझौते से बाहर निकल गए थे।

परमाणु मुद्दे पर, ऐसा लगता है कि डॉनल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुए पिछले बहुराष्ट्रीय समझौते के मामले में आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट गए हैं। इस बीच ट्रंप लगातार बड़े दावे करते रहे हैं कि उन्होंने ईरान की सभी परमाणु हथियार बनाने वाली सुविधाओं को पहले ही नष्ट कर दिया है। हालांकि, उनके अपने प्रशासन के लोगों ने भी कई बार इन दावों का खंडन किया है। युद्ध शुरू होने के बाद से जिस मामले में ट्रंप पूरी तरह विफल रहे हैं, वह महत्वपूर्ण होर्मुज़ जलडमरूमध्य का संचालन है। जब फरवरी के अंत में युद्ध शुरू हुआ था, तब होर्मुज़ जलडमरूमध्य ऐसा खुला समुद्री रास्ता था, जहां किसी भी देश के जहाज लगभग बिना किसी रुकावट के गुजर सकते थे

युद्ध शुरू होने के बाद से यह जलडमरूमध्य ईरान के पूरी तरह नियंत्रण में आ गया है और एक स्थानीय तालाब जैसा बन गया है। यहां तक कि अमेरिका ने भी अपनी शक्तिशाली नौसैनिक टुकड़ियों के साथ इस संकरे समुद्री रास्ते से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की है। यह निश्चित रूप से अमेरिका और उसके अहंकारी राष्ट्रपति के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन ईरानियों के सामने झुकने की यह मजबूरी दुनिया के लिए बहुत महंगी साबित हुई है, क्योंकि होर्मुज़ जलडमरूमध्य के लगभग बंद होने का मतलब है- तेल की आवाजाही पर रोक।

इसके परिणामस्वरूप तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं और दुनिया को युद्ध से पहले की तुलना में तेल के लिए बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। फिर भी ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जलडमरूमध्य पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और, यहां तक कि, इसे अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षाबंधन व विश्व संस्कृत दिवस पर शुभकामनाएं दीं

नई दिल्ली, 28 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देशवासियों को रक्षा बंधन और विश्व संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दीं। उनके एक्स हैंडल पर इस संबंध में दो पोस्ट साझा हुए हैं।

एक रक्षाबंधन से संबंधित श्लोक सुभाषितम् के रूप में है और दूसरा विश्व संस्कृत दिवस से संबंधित श्लोक। उन्होंने लिखा, रक्षाबंधन का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। स्नेह, अपनत्व और आपसी विश्वास की डोर सदैव अटूट बनी रहे, यही कामना है।

बैरियर लेक ओवर फ्लो, दूसरी बार भारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इलाकों के लिए पानी का बहाव बढ़ने के बाद नई चेतावनी जारी की है। बचाव एवं राहतकर्मियों तथा जोखिम वाले इलाकों में मौजूद लोगों से कहा गया है कि हालात बिगड़ने से पहले वे तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। आपदा की शुरुआत नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर टूटने से जुड़े एक हिमखंड-पत्थर के हिमस्खलन के बाद हुई। इसके बाद पानी के तेज बहाव ने रसुवा और नुवाकोट के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया और बड़ी मात्रा में पानी, चट्टानें तथा कीचड़ नीचे की ओर बहा ले गया। बाढ़ के भोतेकोशी और त्रिशूली नदी तंत्र में फैलने से पहले तिमुरे और रसुवागढ़ी सहित कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए। तबाही इतनी ज्यादा है कि जीवित बचे लोगों तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। सड़कें और पुल बह गए हैं, जबकि घर, बाजार, खेत और सरकारी इमारतें कीचड़ की मोटी परतों और मलबे के नीचे दब गई हैं। कई दूरदराज के इलाके अब भी संपर्क से कटे हुए हैं। नेपाल के अधिकारियों ने 910 लोगों के लापता होने की सूचना दी है, जबकि तिब्बत के अधिकारियों ने 558 अन्य लोगों के लापता होने की जानकारी दी है। इस तरह सीमा के दोनों ओर लापता लोगों की कुल संख्या 1,468 हो गई है।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में 290 भारतीय नागरिकों से अब भी संपर्क नहीं हो पाया है। अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। इनमें त्रिशूली- जलविद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी शामिल हैं। तिब्बती क्षेत्र में करीब 200 अन्य भारतीयों ने भी निकासी के लिए मदद मांगी है। बाढ़ से नेपाल के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। सड़क विभाग ने बताया कि नुवाकोट और रसुवागढ़ी के बीच 42 किलोमीटर लंबे मार्ग को कई जगह नुकसान पहुंचा है और कई कंक्रीट पुल बह गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, 35 मोटरेबल पुल, 45 झूला पुल और करीब 40 किलोमीटर पक्की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। त्रिशूली और देवघाट जलविद्युत परियोजनाएं तथा बिजली से जुड़ा अन्य बुनियादी ढांचा भी प्रभावित हुआ है। त्रिशूली- परियोजना स्थल पर नेपाल सेना ने सुरंग के भीतर फंसे करीब 350 कर्मचारियों और श्रमिकों को बचाया। हालांकि, अब भी 100 से अधिक लोगों के वहां फंसे होने की आशंका है।

इस बीच, बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली नेपाल सरकार ने कहा है कि उसे खोज एवं बचाव अभियान के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है। खबरों के मुताबिक, भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने इस अभियान में मदद की पेशकश की है। नेपाल सेंटर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के प्रमुख ने अल जज़ीरा को बताया कि करीब 800 लोगों को हेलीकॉप्टर से और 700 लोगों को जमीन के रास्ते बचाया गया है। बचे हुए लोगों तक राहत सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई जा रही है। लापता लोगों में करीब 644 के विदेशी नागरिक होने की खबर है।

हाईकोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

अकाली दल के साथ गठबंधन ...

■ इन लोकसभा चुनावों में भाजपा 23 विधानसभा क्षेत्रों में पहले, छः पर दूसरे और 16 पर तीसरे स्थान पर रही। इसलिए भाजपा का दावा है उसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अकेले का प्रदर्शन है। उस चुनाव में पंजाब में भाजपा को 18.5 प्रतिशत से अधिक वोट मिले थे, लेकिन राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से उसे एक भी सीट नहीं मिली। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को केवल तीन, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को सात सीटें मिलीं, जबकि दो सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गईं। शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) की हरसिमरत कौर बादल ने बठिंडा लोकसभा सीट बरकरार रखी। उनके पति सुखबीर सिंह बादल संकटग्रस्त एसएडी का नेतृत्व कर रहे हैं।

लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उस चुनाव में भाजपा 23 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही थी। छह सीटों पर वह दूसरे और 16 पर तीसरे स्थान पर रही। इस तरह इन 45 विधानसभा सीटों पर वह एसएडी से आगे थी। सूत्रों के मुताबिक, अब भाजपा के हिस्से में कितनी सीटें होनी चाहिए, इसे लेकर यही 45 सीटों का आंकड़ा चर्चा में है।

सन् 2024 के लोकसभा चुनाव में एसएडी को करीब 13.4 प्रतिशत वोट मिले थे। विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़ों के अनुसार, अकाली दल नौ सीटों पर आगे रहा, पांच पर दूसरे और पांच पर तीसरे स्थान पर रहा। इस लिहाज से उसका प्रदर्शन उसके तत्कालीन कनिष्ठ सहयोगी भाजपा से भी कमजोर रहा।

दोनों दलों को मिलाकर करीब 32 प्रतिशत वोट मिले थे और 64 विधानसभा क्षेत्रों में उनका मजबूत प्रदर्शन रहा था।

भाजपा का आकलन है कि यदि दोनों दल साथ होते तो गठबंधन 57 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रहता। यह 117 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के आंकड़े से केवल दो सीट कम है। सूत्रों का कहना है कि दोबारा बना गठबंधन सत्ता विरोधी माहौल का लाभ उठाकर आप को कडी चुनौती दे सकता है। राज्य में कांग्रेस अब भी गुटबाजी से जूझ रही है।

एसएडी और भाजपा 1996 से 2020 तक गठबंधन में रहे। 1997 के विधानसभा चुनाव में दोनों ने भारी जीत दर्ज की थी। एसएडी को 75 और भाजपा को 18 सीटें मिली थीं। 2007 में अकाली दल ने 49 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा 19 सीटों तक पहुंच गई। 2012 में गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटकर इतिहास बनाया, जिसमें एसएडी को 56 और भाजपा को 12 सीटें मिलीं।

लेकिन इस बार एक और अहम सवाल यह है कि कौन-सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। आमतौर पर भाजपा ने हिंदू बहुल शहरी क्षेत्रों में और अकाली दल ने ग्रामीण इलाकों में चुनाव लड़ा है, जहां सिख आबादी अधिक है। लेकिन इस बार अकाली दल कुछ अर्ध-शहरी सीटों पर भी चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है, जहां भाजपा को मजबूत माना जाता है। भाजपा ने अपनी राज्य इकाई में शीर्ष पदों पर जाट सिख नेताओं को नियुक्त किया है और वह ग्रामीण पंजाब में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है। गठबंधन चर्चा से परिचित लोगों के मुताबिक, सीटों के समझौते में विशेष रूप से इन क्षेत्रों को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद, चुनाव में मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार के साथ उतरने का सवाल है। माना जा रहा है कि भाजपा इसके पक्ष में नहीं है। अकाली दल चाहता है कि सुखबीर सिंह बादल को गठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। सूत्रों के अनुसार, कुछ भाजपा नेताओं का मानना है कि उनकी खराब छवि सफलता के रास्ते में बाधा बन सकती है। सुखबीर सिंह बादल अपने पिता और दिवंगत मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के कार्यकाल में उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं।

लेकिन, अगर गठबंधन बनता है और चुनाव जीतता है, तो मुख्यमंत्री पद अकाली दल के पास जाएगा, क्योंकि वह अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगा। भाजपा उपमुख्यमंत्री पद पर दावा कर सकती है।

फिलहाल दोनों ही दल गठबंधन की घोषणा को लेकर जल्दबाजी में नहीं हैं। भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष के हालिया पंजाब दौरे के दौरान, सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। भाजपा राज्यभर में नशे के मुद्दे पर एक यात्रा निकालने की भी योजना बना रही है, जिसमें केन्द्र सरकार की हालिया उपलब्धियों को भी रेखांकित किया जाएगा।

बिलासपुर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहुंचा। विमान में सवार सभी 60 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को भी चोट नहीं आई है।

इस घटना के बाद विमान में आई तकनीकी खराबी के कारण बिलासपुर से प्रयागराज जाने वाली कनैक्टिंग फ्लाइट को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। फ्लाइट रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।

खाद्य व पेय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को लेकर सचेत हो सकेंगे। नेस्ले, पेप्सिको और कोका-कोला जैसी कंपनियां इस कदम का विरोध कर रही हैं, क्योंकि इससे बिक्री पर असर पड़ने की आशंका है।

सुप्रीम कोर्ट में एफएसएसएआइ की एक फाइलिंग का हवाला देते हुए रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि चेतावनी लेबल पर अधिक फैट या वसा, अधिक शुगर, अधिक नमक या बहुत ज्यादा मीठा ड्रिंक जैसी जरूरी जानकारी लिखी होगी, ताकि ग्राहक आसानी से उन उत्पादों की पहचान कर सकें जिनमें बताए गए न्यूट्रिएंट्स अधिक हों।

सोनिया गांधी की आत्मकथा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पब्लिशर ने यह जरूर स्वीकार किया कि वे "पुस्तक प्रकाशित करने के लिए उत्सुक" थे। उन्होंने कहा कि लेखकों की किताबों के तथ्यों की जांच करना और उन्हें सुझाव देना उनकी जिम्मेदारी है, इससे संकेत मिलता है कि सोनिया गांधी के साथ पुस्तक को लेकर बातचीत हुई थी।

प्रकाशक ने कहा, "एक प्रकाशक के रूप में तथ्यों की जांच करना और लेखकों को उनकी पुस्तकों के हित में सुझाव देना हमारा अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। यह प्रकाशन प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है।"

हालांकि, प्रकाशक ने लेखिका के साथ हुई बातचीत का विवरण बताने से इनकार कर दिया।

बयान में कहा गया, संबंधित बातचीत के दौरान पैनग्विन रैंडम हाउस इंडिया का रुख यही रहा कि हम पुस्तक प्रकाशित करने के लिए इच्छुक और उत्सुक थे। "हम लेखिका के साथ हुई गोपनीय बातचीत पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।"

पैनग्विन के इस मामले से बाहर होने के बाद अब कई भारतीय प्रकाशक पुस्तक के प्रकाशन अधिकार हासिल करने की दौड़ में हैं। खबर है कि हार्पर कॉलिन्स भारत में पुस्तक के प्रकाशन और वितरण के लिए समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है।

अमेरिकी प्रकाशन जगत की बड़ी कंपनी और पैनग्विन रैंडम हाउस की एक इकाई अल्फ्रेड ए. नॉफ ने घोषणा की है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का संस्मरण 10 नवंबर को प्रकाशित होगा।

नॉफ के माध्यम से जारी एक बयान में सोनिया गांधी ने कहा, मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन बहुत कम कहानियां उनके उद्देश्यों, उनके कार्यों और उनकी मानवीय कमजोरियों की सच्चाई तक पहुंच पाई हैं। कई मायनों में यह पुस्तक उनकी मानवीयता को श्रद्धांजलि है। मेरी कहानी पाठकों को उस खूबसूरत देश में हुए सामाजिक और राजनीतिक बदलावों का एक अनोखा नजरिया भी देती है, जिसे मैंने अपना देश माना है और जहां मैं छह दशकों से रह रही हूं।

"बिलॉन्गिंग" में सोनिया गांधी ने अपने जीवन के उस दौर के बारे में लिखा है, जब 1984 में उनकी सास इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और उनके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, जिनकी सात साल बाद हत्या कर दी गई।

आखिरकार सोनिया गांधी राजनीति में उतरीं और कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली नेता बनीं। उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। सन् 2014 में उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भाजपा से सत्ता हार गई।

उन्होंने कहा, "अपने जीवन के बारे में लिखना मेरे लिए आसान नहीं था। इसका मतलब था- खुद को खोलना और उन पलों तथा अनुभवों को साझा करना, जिन्हें मैंने हमेशा अपने भीतर गहराई से संभालकर रखा था। लेकिन जैसे-जैसे मैंने खुद को राजनीतिक क्षेत्र से दूर किया और पीछे मुड़कर उन सभी चीजों को देखा जिन्हें मैंने देखा था, मेरे जीवन में प्रेम और निष्ठा का जो धागा लगातार जुड़ा रहा, वह धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगा। यह कहानी इटली के एक छोटे शहर में मेरे सरल बचपन से लेकर भारत में राजीव गांधी की पत्नी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू के रूप में बिताए जटिलता से भरे वर्षों तक की है।" पब्लिशिंग हाउस किताब में बदलाव चाहता था। पर, अगर यह किताब बिना बदलाव बाजार में आ जाती, और इसमें वही सब कुछ लिखा होता, जो सोनिया गांधी लिखना चाहती थीं, तो इससे आरएसएस-भाजपा के पूरे तंत्र को शर्मिंदा होना पड़ता, खासकर तब, जबकि प्रधानमंत्री की छवि तेजी से कमज़ोर हो रही है और विपक्ष के नेता की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908